सप्तदश

बिहार विधान सभा

दशम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 17 कार्तिक, 1945 (श०)
08 नवम्बर, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 09

(1)	ग्रामीण कार्य विभाग	01
(2)	ग्रामीण विकास विभाग	05
(3)	पथ निर्माण विभाग	01
(4)	पंचायती राज विभाग	02
	कुल योग --	09

कार्रवाई करना

7. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--हिन्दी समाचार-पत्र हिन्दुस्तान दिनांक 22 अक्टूबर, 2023 के अंक में प्रकाशित खबर के शीर्षक "फैसला ग्रामीण सड़कों की ऑनलाइन जानकारी नहीं दे रहे इंजीनियर" के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के तहत बनी सड़कों की शत-प्रतिशत जानकारी भवन पोर्टल पर अपलोड करना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में सभी कार्य प्रमंडलों में बनी सड़कों की जानकारी विगत दो वर्षों में ऑनलाइन नहीं होने के कारण सड़कों की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिल पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के तहत बनी सड़कों के ऑनलाइन भवन पोर्टल पर नहीं करने वाले 10 कार्य प्रमंडलों के पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा समय-सीमा के अंदर डाटा अपलोड कबतक करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

8. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "सूबे के 10 जिलों में पी0एम0 आवास योजना की स्थिति खराब" के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत राज्य के 10 जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति काफी कम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित जिलों में पी0एम0 आवास योजना की स्वीकृति मिलने के बावजूद लम्बित आवास को पूर्ण करने की संख्या कम है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार खंड (1) में वर्णित जिलों में पी0एम0 आवास योजना की प्रगति बढ़ाने एवं लम्बित आवास को पूर्ण करने हेत कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूर्ण कराना

9. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "दो साल में ही होना था निर्माण छः महीना बाकी, 25 प्रतिशत हुआ काम" के आलोक में क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य सीमा, मिर्जा चौकी, मुंगेर फोरलेन 124 किलो मीटर उच्च पथ का 3,792 करोड़ रुपये की लागत से 2 वर्षों में निर्माण कार्य पूर्ण करने के अनुबंध के विरुद्ध माह अप्रील, 2022 में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया जो डेढ़ वर्ष बीत जाने के बावजूद मात्र 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराने का औचित्य क्या है ?

दोषियों पर कार्रवाई

10. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "पंचायतों में 5 प्रतिशत ही सोलर स्ट्रीट लाईट लगी" के आलोक में क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के गाँवों की गलियों को रौशन करने के लिये 15 सितम्बर, 2022 को सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना की शुरूआत की गई थी जिसके अन्तर्गत दो वर्षों में 11 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन आजतक मात्र 52463 हजार लाईट ही लगी है तथा राज्य के पंचायतों के मुखिया से यह योजना हस्तगत कर विभाग द्वारा लाइट लगाने के लिये 13 निजी एजेंसियों को चयन किया गया था, यदि हाँ, तो सरकार निजी एजेन्सियों को रद्द करते हुये कबतक उपरोक्त योजना विभागीय स्तर पर कराने एवं लापरवाही के लिये दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया राशि देना

11. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 जुलाई, 2023 को प्रकाशित खबर "मनरेगा में बढ़ते बकाये से चरमराई व्यवस्था" को ध्यान में रखकर क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर, बक्सर सहित पहरे राज्य में मनरेगा के तहत अलग-अलग मद में वर्ष 2015 से अबतक कुल 1,146 करोड़ रुपया बकाया हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि मनरेगा के तहत समय पर भुगतान नहीं होने से बाजार या वेंडर से सामग्री नहीं मिल रही हैं जिसे वजह से पौधारोपण, गैबियन निर्माण आपूर्ति, नाली-गली मरम्मत एवं गौशाला निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार, मनरेगा के तहत अलग-अलग मद में बकाया राशि को कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का कार्यान्वयन

12. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0जा0))--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 जुलाई, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "मनरेगा में आठ लाख से ज्यादा योजनाएँ लम्बित" के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में मनरेगा में अभीतक 8 लाख से ज्यादा योजनाएँ लम्बित होने के कारण मजदूरों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो मरनेगा की 8 लाख योजनाएँ लम्बित रहने का क्या औचित्य है ?

भुगतान करना

13. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2009 तक मनरेगा की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उनके भुगतान का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्राप्त था ;

(3) क्या यह बात सही है कि पंचायतों की मनरेगा की योजनाओं के भुगतान का अधिकार वर्तमान में संविदा पर नियोजित प्रोग्राम पदाधिकारियों को दिया गया है जो मनरेगा और वित्तीय दोनों नियमों के विपरीत है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो प्रशासनिक अधिकार प्राप्त ग्राम पंचायतों से मनरेगा की योजनाओं के भुगतान के अधिकार वंचित करने का क्या औचित्य है ?

कचरा संग्रहण केन्द्र का निर्माण

14. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 मई, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "138 पंचायतों में भेजी गई राशि, मात्र 97 पंचायतों में हो रहा कचरे का उठाव" को ध्यान में क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत अब गाँव में भी कचरा प्रबंधन की कवायद की गई है, जिससे जिले के 258 पंचायत के विरुद्ध अबतक 138 पंचायतों में राशि उपलब्ध करायी जिससे अबतक 97 पंचायतों में कचरा उठाव शुरू किया गया है यहाँ कर्मियों को किसानों से कचरा संग्रहण करने के लिये मशक्कत करनी पड़ रही है। जिन गाँव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं किया गया है तो कहाँ संग्रहण केन्द्र का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सभी पंचायतों में कबतक कचरा संग्रहण केन्द्र का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण

15. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "10 साल पहले आवंटित 1.87 लाख आवास का निर्माण अब भी अधूरा" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक निर्धारित तीन वर्षों में राज्य कुल 2242345 इंदिरा आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद आजतक 1.87 लाख आवास का निर्माण अधूरा पड़ा है जिसमें अररिया में 20315, गया में 7980, पूर्वी चम्पारण में 8478 अपूर्ण आवास है, यदि हाँ, तो सरकार 10 वर्ष बीत जाने के बाद आजतक उक्त आवास का निर्माण पूर्ण नहीं होने का क्या कारण है और ससमय कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 8 नवम्बर, 2023 (ई0) ।

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 58(एल0ए0), 2023-24-डी0टी0पी0-550